पर रोक लगाने के लिये कोई नया तथा प्रभावी कानून बनाने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कानून की अवहेलना करने वाले उद्योगपतियों/मालिकों के विरुद्ध कारवाई के लिये प्रस्तावित कानून में क्या प्रावधान होगा और उक्त कानून कब तक लागू किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बालकों की संख्या 11.28 मिलियन है सर्वाधिक संख्या में कामकाजी बालक वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1.66 मिलियन काम काजी बालक थे। वे अन्य राज्य जिनमें कामकाजी बालकों की जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है, वे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बालकों के नियोजन के संबंध में उद्योग-विशिष्ट सूचना दसवर्षीय जनगणना में सूचित नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) सरकार की नीति सभी व्यवसायों और उद्योगों से बाल श्रम का उन्मूलन करने की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। तथापि, सभी प्रकार के उद्योगों में बाल श्रम के नियोजन को पूर्ण प्रतिबंध लगाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

Welfare measure for Tendu Leaf collectors

2573. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of Tendu Beedi leaf collectors in the country;

(b) whether any census has been conducted to identify and enumerate the number of Tendu leaf collectors, State-wise;

(c) whether housing and other benefits are being extended to m llions of Tendu leaf collector-.; and

(d) if so, the details o£ welfare measures for their benefit?

THF MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (5HRI M. P. VEERENDRV KUMAR); (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House-

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना औद्योगिक एककों को बंद किया जाना

2574. श्री सतीश चंद्र अग्रवाल :
श्री अमोल जोगी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार औद्योगिक एककों को पूर्व अनुमति बिना बंद करने के उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रमिकों के संरक्षण पर विचार किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में श्रमिकों की भी राय जानी गई है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Minimum wages to workers

2575. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what steps have been taken by Government to see that the notified